

एम/एस जीएमआर एनर्जी लिमिटेड

बनाम

सीमा शुल्क आयुक्त

(सिविल अपील संख्या 4920/2007)

27 अक्टूबर, 2015

[ए. के. सिकरी और आर. एफ. नरीमन, जे. जे.]

सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का निर्धारण) नियम, 1988- नियम 4 आरडब्ल्यू आर 9(1)(डी) और (ई), नियम 10 - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962-धारा 46 (4) :

लेन-देन मूल्य-बिजली संयंत्र के गैस टर्बाइन हॉट सेक्शन के पुर्जों का आयात, जिन्हें विदेशी कंपनी के साथ किए गए दीर्घकालिक आश्वस्त पुर्जों की आपूर्ति समझौते (एल. टी. ए. पी. एस. ए.) के तहत 12,500 घंटे के उपयोग के बाद बदलना पड़ता है-मूल्यांकन-अपीलकर्ता ने एल. टी. ए. पी. एस. ए. कंपनी के साथ पुर्जों की सेवा और आपूर्ति के लिए एक समझौता किया-दो प्रवेश बिलों के तहत उक्त संयंत्र के विभिन्न हिस्सों का आयात-ऐसे पुर्जों की पहचान की गई जिन्हें शिपिंग बिलों की आड़ में कंपनी को फिर से निर्यात किया जाना था, इससे पहले कि आयात शुल्क अधिकारियों को बदले गए पुर्जों के आयात के लिए प्रस्तुत किए गए प्रवेश के उपरोक्त

बिल-अपीलकर्ता ने प्रविष्टि के उक्त बिलों में घोषित मूल्य के आधार पर सीमा शुल्क का भुगतान किया, लेकिन कुछ भी नहीं किया।

छूट अधिसूचना-छूट का लाभ-प्रवेश के बिलों के तहत माल का आयात-छूट अधिसूचना-अपीलकर्ता-आयातक-अपीलकर्ता द्वारा आयात के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने का दावा-विभाग द्वारा अपीलार्थी को छूट अधिसूचना के लाभ से इनकार, हालांकि, न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी गई-अपील पर कहा गया: एक बार जब अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं कि माल नवीनीकरण के लिए आवश्यक है, तो सीमा शुल्क विभाग को मामले में गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं होती है और बाल की खाल और शब्दार्थ संबंधी बारीकियों द्वारा छूट अधिसूचना के लाभ से इनकार किया जाता है-न्यायाधिकरण आयुक्त के निष्कर्ष को रद्द करने में सही था।

निर्धारिती की अपील को अनुमति देते हुए और राजस्व की अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने

अभिनिर्धारित किया: सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 1988 के नियम 4 और 9 केवल उस स्थिति में लागू होंगे जब आयातित वस्तुओं को भारत को निर्यात करने के लिए "बेचा" जाता है। तथ्यों पर, कोई बिक्री नहीं है। एल. टी. ए. पी. एस. ए. के तहत जो कुछ भी होता है वह यह है कि बिजली संयंत्र के चलने के कुछ निश्चित घंटों के बाद पुर्जों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदल दिया

जाता है। इस मामले में, निर्धारिती यह प्रस्तुत करने में सही था कि न तो नियम 4 और न ही नियम 9 लागू होंगे, क्योंकि नियम 4, यदि लागू होता है, तो नियम 9 भी लागू होता है। नियम 4 (2) (जी) और नियम 9 (1) (डी) केवल उन्हीं वस्तुओं को संदर्भित करते हैं जो आयात की जाती हैं और उन वस्तुओं को नहीं जो आयातित वस्तुओं के लिए बहुत पहले आयात की गई हों। इसलिए, जो आवश्यक है वह यह है कि खरीदार द्वारा बहुत ही आयातित वस्तुओं की पुनः बिक्री, निपटान या उपयोग से उत्पन्न होने वाली आय होनी चाहिए। विभाग का मामला यह है कि ये उप-नियम केवल इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उस समय पहले बिक्री होती थी जब पूरे संयंत्र का आयात किया जाता था और बाद में खरीदार द्वारा संयंत्र की स्थापना के बहुत बाद आयातित वस्तुओं का निपटान किया जाता था। चूंकि यह स्पष्ट है कि बहुत ही आयातित वस्तुओं की बाद में कोई पुनः बिक्री, निपटान या उपयोग नहीं है-जो कि दिनांकित दो प्रविष्टि बिलों के तहत आयातित पुर्जे हैं, निर्धारिती अपने तर्क में सही है कि किसी भी मामले में इनमें से कोई भी उप-नियम तत्काल मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। समान रूप से, नियम 9 (1) (ई) का इस कारण से कोई आवेदन नहीं होगा कि खरीदार द्वारा विक्रेता को आयातित वस्तुओं की बिक्री की शर्त के रूप में वास्तव में कोई अन्य भुगतान नहीं किया गया है या नहीं किया जाना है। इसके अलावा नियम 5 का कोई उपयोग नहीं होगा। [पैरा 11,12] [124-ई-एच; 125-ए-डी; 126-ए]

1.2 आयुक्त के आदेश के साथ-साथ न्यायाधिकरण के आदेश का आधार एल. टी. ए. पी. एस. ए. का खंड 2.8 है। यह स्वीकार किया जाता है कि विक्रेता को केवल खरीदार को प्रत्येक नवीनीकृत हिस्से के वृद्धिशील मूल्य के बारे में "जानकारी" देनी होती है ताकि सीमा शुल्क ऐसे प्रत्येक नवीनीकृत हिस्से के वृद्धिशील मूल्य तक सीमित हो सके। तथ्यों पर, निर्धारिती ने कारण दर्शाओ नोटिस के अपने जवाब में, यह स्पष्ट कर दिया है कि आयातित वस्तुओं की कीमत एक घूमने योग्य विनिमय कार्यक्रम मूल्य थी जो एक सामान्य समान मूल्य था जिस पर ऐसे पुर्जों की आपूर्ति जी. ई., यू. एस. ए. द्वारा दुनिया भर में की गई थी। यह एक ऐसे दस्तावेज़ से स्पष्ट है जिस पर कारण दर्शाएँ नोटिस द्वारा ही भरोसा किया गया था, जो जी. ई. के अनुमोदन योग्य विनिमय कार्यक्रम से संबंधित था। उक्त दस्तावेज़ से यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्काल मामले में प्रवेश के बिलों के साथ चालान में बताई गई कीमतें सूची इकाई कीमतें या सूची मूल्य हैं। कल्पना के किसी भी विस्तार से उन्हें पुनः निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्य को ध्यान में रखने के बाद की कीमतें नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में, आयुक्त और न्यायाधिकरण दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलत थे कि चालान मूल्य केवल एक वृद्धिशील मूल्य मूल्य है न कि जीई, यू. एस. ए. द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं की कीमत। तथ्यों के आधार पर यह मामला होने के कारण, आयुक्त के आदेश और

न्यायाधिकरण के आदेश दोनों को केवल इसी आधार पर दरकिनार करना होगा। [पैरा 14,15] [126-सी-ई; 127-सी-डी]

1.3 धारा 46 (4) और नियम 10 (1) (ए) का एक संयुक्त पठन, आयातक पर प्रवेश पत्र प्रस्तुत करते समय इसकी सामग्री की सच्चाई के बारे में घोषणा की सदस्यता लेना और आयातित वस्तुओं से संबंधित चालान को उचित अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्धारिती ने इस शर्त को पूरा किया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्धारिती को मैसर्स जी. ई., यू. एस. ए. के साथ किए गए एल. टी. ए. पी. एस. ए. का भी खुलासा करना चाहिए था, जो आयातित वस्तुओं के वास्तविक मूल्य और अन्य विवरणों को उचित अधिकारी को प्रकट करता, जो तब एक सूचित मूल्यांकन कर सकते थे। एल. टी. ए. पी. एस. ए. एक ऐसा दस्तावेज होगा जो अधिनियम की धारा 17 (3) के साथ पठित नियम 10 (1) (बी) के अंतर्गत आएगा। धारा 17 (3) और नियम 10 (1) (बी) के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उचित अधिकारी आयातक से आयातित माल के संबंध में कोई भी अनुबंध प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप आयातक ऐसा अनुबंध प्रस्तुत करेगा। तथ्यों पर उचित अधिकारी ने निर्धारिती को आयातित वस्तुओं के संबंध में कोई अनुबंध प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा है। इस प्रकार, नियम 10 का कोई उल्लंघन नहीं है। न्यायाधिकरण के

फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 19-22] [128-D-G; 129-C, D, E]

1.4 आवश्यक प्रमाणपत्र के साथ-साथ कर्नाटक सरकार के प्रधान सचिव की सिफारिश दोनों को उचित परिप्रेक्ष्य में निपटाया गया था। इबुनाल यह कहने में काफी सही है कि एक बार जब ये अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं कि विवादित सामान के नवीनीकरण की आवश्यकता है, तो सीमा शुल्क विभाग को मामले में गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है और बाल-विभाजन और शब्दार्थ संबंधी बारीकियां छूट अधिसूचना के लाभ से इनकार करती हैं। न्यायाधिकरण द्वारा आयुक्त के निष्कर्ष को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, सी. ई. एस. टी. ए. टी. के आदेश के पैराग्राफ 11 को उपखंड (ii) और (vi) को छोड़कर अलग रखा गया है। [पैरा 25] [132-एफ-जी]

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील संख्या 4920/2007

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, बेंगलोर के निर्णय और आदेश दिनांक 03.08.2007 से अपील संख्या सी/347/06

उपस्थित पक्षकारों के लिए वी. श्रीधरन, के. राधाकृष्णन, एम. पी. देवनाथ, एस. वासुदेवन, एल. चरणया, शगुन अरोड़ा, हेमंत बजाज, आनंद

के., आदित्य भट्टाचार्य, रुपेश कुमार, शिरीन खजुरिया, रितेश कुमार, प्रतीक, बी. कृष्ण प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने दिया-1. सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित दिनांक 3.8.2007 के विवादित फैसले के खिलाफ दो अपील दायर की गई हैं। निर्धारिती मेसर्स जी. एम. आर. एनर्जी लिमिटेड द्वारा दायर अपील नैफथा आधारित बिजली संयंत्र के गैस टर्बाइन हॉट सेक्शन के पुर्जों के आयात के उचित मूल्यांकन से संबंधित है, जिन्हें जी. ई., यू. एस. ए. के साथ 20 दिसंबर, 2000 को किए गए दीर्घकालिक आश्वस्त पुर्जों की आपूर्ति समझौते (जिसे इसके बाद "एल. टी. ए. पी. एस. ए." के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत 12,500 घंटे के उपयोग के बाद बदला जाना है। राजस्व की अपील स्वयं इस बात से संबंधित है कि क्या निर्धारिती 2002 की छूट अधिसूचना संख्या 21 दिनांक 1.3.2002 का लाभ उठाने का हकदार है, जो दिनांक 25.6.2003 के दो प्रविष्टि बिलों के तहत आयातित वस्तुओं के संबंध में है।

निर्धारिती की अपील

2. अपीलार्थी ने पाँच गैस टर्बाइनों के साथ एक नाफथा आधारित बिजली संयंत्र का आयात किया था जिसे बिजली उत्पादन के उद्देश्यों के लिए मेंगलोर के पास एक तानिर बवी गाँव में एक नदी में तैरने वाले बजरे पर लगाया गया था। उक्त बिजली संयंत्र की क्षमता 220 मेगावाट है और

उत्पन्न पूरी बिजली को कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ग्रिड में अपलोड किया जाता है। बिजली संयंत्र को अच्छी स्थिति में रखना पड़ा क्योंकि केपीटीसीएल के साथ अनुबंध उन्हें लगातार बिजली की आपूर्ति करने का है। इस उद्देश्य के लिए, अपीलार्थी ने जी. ई., यू. एस. ए. के साथ पुर्जों की सेवा और आपूर्ति के लिए एक समझौता किया, जो एक दीर्घकालिक आश्वस्त पुर्जों की आपूर्ति समझौता दिनांक 12.12.2000 (इसके बाद "एल. टी. ए. पी. एस. ए". के रूप में संदर्भित) है। उक्त समझौते के संदर्भ में, अपीलार्थी को या तो निकाले गए घंटे के शुल्क या रखरखाव शुल्क के आधार पर भुगतान करना था। उक्त संयंत्र के गैस टर्बाइन हॉट सेक्शन के विभिन्न हिस्सों, जिन्हें एल. टी. ए. पी. एस. ए. के तहत आयात किया जाना था, को 12,500 घंटे के काम के बाद 25.6.2003 दिनांकित दो बिलों के तहत आयात किया गया था। जिन पुर्जों को बदलने की आवश्यकता के रूप में पहचाना गया था, उन्हें मई, 2003 के महीने के शिपिंग बिलों की आड़ में जी. ई., यू. एस. ए. को फिर से निर्यात किया गया था, इससे पहले कि प्रतिस्थापित पुर्जों के आयात के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को 25.6.2003 के दो प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए गए थे। अपीलार्थी ने उक्त प्रवेश पत्रों में घोषित मूल्य के आधार पर सीमा शुल्क का भुगतान किया, लेकिन इन चालानों के आधार पर जी. ई. को कोई भुगतान नहीं किया क्योंकि उनका भुगतान पहले ही निर्धारित घंटे के शुल्क के आधार पर किया जा चुका था। आयात के समय प्रस्तुत

दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद सीमा शुल्क विभाग द्वारा उक्त आयात का मूल्यांकन पूरा किया गया था।

3. इसके बाद, आई. डी. 1 दिनांकित एक कारण दर्शाओ नोटिस द्वारा, सीमा शुल्क विभाग ने नियम 4 (2) (जी) और नियम 9 (1) (डी) और 9 (1) (ई) की सहायता मांगी क्योंकि वे प्रासंगिक समय पर थे ताकि आयातित वस्तुओं के मूल्य का एक तिहाई हिस्सा चालान मूल्य में जोड़ा जा सके क्योंकि यह उन भागों की राशि का प्रतिनिधित्व करता था जिन्हें जी. ई., यू. एस. ए. को वापस बदल दिया गया था और फिर से निर्यात किया गया था। कारण दर्शाओ नोटिस अनिवार्य रूप से अपीलार्थी के वित्त प्रबंधक श्री नरेश मनचंदा और कंपनी के महाप्रबंधक श्री सिद्धार्थ द्वारा दिए गए बयानों पर आधारित था। इसमें कहा गया है:

"29. की गई जाँच से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:

(i) मैसर्स जी. ई. एल., बेंगलोर ने मैसर्स जी. ई., यू. एस. ए. के साथ तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनमें बार्ज माउंटेड पावर प्लांट के गैस टर्बाइनों के रखरखाव और रखरखाव के लिए एक दीर्घकालिक आश्वस्त पुर्जों की आपूर्ति समझौता (एल. टी. ए. पी. एस. ए.) शामिल है।

(ii) इस समझौते में गर्म पथ के पुर्जों के लिए एक स्वीकार्य विनिमय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है, जो एक आवश्यक प्रकृति के भाग हैं, जिन्हें उपयोग के लिए 12,500 घंटे की निर्धारित अवधि के बाद

या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने पर पहले बदलने की आवश्यकता होती है।

(iii) इन गर्म पथ के पुर्जों को उनके उपयोग के बाद गैस टर्बाइनों से हटा दिया जाता है। समझौते के अनुमोदन योग्य विनिमय कार्यक्रम के तहत, एक बार हटाए जाने के बाद, गर्म पथ के पुर्जे मैसर्स जीई, यूएसए की संपत्ति बन जाते हैं और भारतीय फर्म मिस जीईएल को उन्हें मिस जीई को निर्यात करने की आवश्यकता होती है। इन भागों की प्राप्ति पर, मैसर्स जी. ई. उनकी स्थिति की पुष्टि करता है और तदनुसार उनका नवीनीकरण किया जाता है। इस तरह के नवीनीकृत भागों से नए भागों में कोई अंतर नहीं पड़ता है और ये सभी मामलों में समान हैं। मिस जी. ई., यू. एस. ए. अपने ग्राहकों को इन पुर्जों की आपूर्ति करता है। मैसर्स जी. ई. एल. जैसे ग्राहकों को यह नहीं पता कि उन्हें आपूर्ति किए गए पुर्जे नए हैं या नवीनीकृत।

(iv) जब मैसर्स जी. ई. एल. इन उपयोग किए गए पुर्जों का निर्यात करता है, तो किए गए निर्यात के लिए कोई निर्यात बिक्री आय प्राप्त नहीं होती है और मैसर्स जी. ई., यू. एस. ए. मैसर्स जी. ई. एल. को कोई भुगतान नहीं करता है। हालांकि, जब मैसर्स जी. ई. एल. हॉट पाथ भागों का आयात करता है, तो निर्धारित मूल्य अनुमोदन योग्य विनिमय कार्यक्रम पर आधारित होता है। मैसर्स जी. ई. एल. द्वारा लौटाए गए उपयोग किए

गए गर्म पथ के पुर्जों की लागत का ध्यान रखा जाता है, और एक कमी दी जाती है और उसके बाद, कीमत तय की जाती है।

(v) इस प्रकार मैसर्स जी. ई., यू. एस. ए. द्वारा मैसर्स जी. ई. एल., बेंगलोर को प्रस्तुत किया गया चालान अनुमोदन योग्य विनिमय कार्यक्रम के आधार पर एक रियायती मूल्य है। अनुमोदन योग्य विनिमय कार्यक्रम के तहत कीमतें हालांकि रियायती कीमतें हैं, वे व्यापक रूप से उपयोग में हैं और इन्हें लोकप्रिय रूप से सूची मूल्य या प्रकाशित मूल्य सूची कहा जाता है।

(vi) प्रवेश पत्र के साथ सीमा शुल्क को प्रस्तुत किया गया चालान केवल अनुमोदन योग्य विनिमय मूल्य है। निर्यातित प्रयुक्त गर्म पथ भाग की लागत के लिए दी गई कमी चालान में परिलक्षित नहीं होती है। इसलिए, सीमा शुल्क मूल्यांकन के उद्देश्य से, घोषित मूल्य के लिए वापस किए गए हॉट पाथ भाग की लागत के बराबर जोड़ के रूप में समायोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें छूट दी गई थी।

(vii) यह कटौती। छूट अनुमोदन योग्य विनिमय कार्यक्रम के तहत सूची मूल्य के एक तिहाई की सीमा तक है। मैसर्स जी. ई., यू. एस. ए. चाहता था कि मैसर्स जी. ई. एल. भारत से निर्यात के समय इस मूल्य की घोषणा करे।

(viii) मेसर्स जी. ई. एल. ने मेसर्स जी. ई., यू. एस. ए. के साथ किए गए समझौतों को सीमा शुल्क विभाग को प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने अनुमोदन योग्य विनिमय कार्यक्रम और समझौतों के तहत किए गए भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी को दबा दिया।

(ix) हटाए गए पुर्जे मैसर्स जी. ई., यू. एस. ए. की संपत्ति बन जाते हैं और मैसर्स जी. ई. एल. के पास मैसर्स जी. ई. को निर्यात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। मेसर्स जी. ई., यू. एस. ए. द्वारा हॉट पाथ पुर्जे का आयात। लौटाए गए पुर्जे की लागत को आयातित पुर्जे के मुकाबले समायोजित किया जाता है। इस प्रकार आयात एक सशर्त बिक्री है और लौटाए गए पुर्जे की लागत विक्रेता को उपार्जित होती है। यह स्थिति सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम, 1988 में 9 (1) (डी) और (ई) द्वारा कवर की गई है।

(x) इस सूचना में चर्चा किए गए साक्ष्यों को देखते हुए, घोषित मूल्यों को अस्वीकार करने की आवश्यकता है और इसे सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 के नियम 4 के तहत सही लेनदेन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

4. कहा जाता है कि सीमा शुल्क से लगभग 4.20 करोड़ रुपये की चोरी हुई थी। माल को ज़ब्त करने योग्य कहा जाता था और अंततः निम्नलिखित मांग की जाती थी: -

“30. अब, इसलिए, एम/एस। जी. एम. आर. एनर्जी लिमिटेड, बेंगलोर से सीमा शुल्क आयुक्त, सी. आर. बिल्डिंग, पी. बी. N0.5400, क्वींस रोड, बेंगलोर-560001 को कारण बताने के लिए कहा जाता है कि क्यों:

(ए) सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 1988 के नियम 9 (1) (डी) और (ई) के साथ पठित नियम 4 के तहत और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के संदर्भ में 5 प्रवेश पत्रों (अनुलग्नक-11 में सूचीबद्ध) द्वारा कवर किए गए आयातित वस्तुओं का मूल्य, रुपये 45,24,23,850/- (केवल पैंतालीस करोड़ चौबीस लाख तेइस हजार आठ सौ पचास रुपये) पर फिर से निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए,

(बी) अधिसूचना संख्या 21/2002- सीयूएस दिनांक 01.03.2002 के तहत छूट के लाभ को प्रवेश पत्र संख्या संख्या 9140 दिनांक 25.06.2003 और 598675 दिनांक 12.04.2004 के संबंध में अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

(सी) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 (1) के प्रावधान के तहत कुल 521/- रुपये का शुल्क (सात करोड़ छत्तीस लाख अड़सठ हजार पांच सौ इकतीस रुपये केवल) कम भुगतान किया गया आयात शुल्क

होने की मांग नहीं की जानी चाहिए, जैसा कि इस सूचना के अनुलग्नक में विस्तार से बताया गया है।

(डी) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 एबी के तहत उपर्युक्त शुल्क राशि पर लागू दर (ओं) पर ब्याज की मांग नहीं की जानी चाहिए।

(ई) उपरोक्त (ए) में इंगित माल को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 (एम) के तहत ज़ब्त नहीं किया जाना चाहिए।

(च) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 (एम) के तहत ज़ब्त करने के दायित्व से डी के अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 (एम) के तहत ज़ब्त किए जाने के दायित्व के अलावा, उपरोक्त (ए) पर इंगित माल का हिस्सा बनने वाले बिल ऑफ़ एंट्री Nos.9140 दिनांक 25.06.2003 और 598675 दिनांक 12.04.2004 के तहत आयातित और साफ़ किए गए सामान को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 (ओ) के तहत ज़ब्त नहीं किया जाना चाहिए।

(छ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 (ए) और/94 की धारा 114 ए के तहत जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।

5. निर्धारिती द्वारा भेजे गए कारण बताएँ नोटिस के जवाब में लगाए गए सभी आरोपों पर विवाद किया गया और विशेष रूप से निम्नानुसार कहा गया:

"एच. बीमा के लिए घोषित मूल्य आयातित वस्तुओं के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा संदर्भ है।

एच. 1 यह सर्वविदित है कि आयातित माल हमेशा एक समुद्री बीमा पॉलिसी या वायु बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किए जाते हैं, जैसा भी मामला हो। इस तरह का बीमा संबंधित पक्षों की दृष्टि से आवश्यक है ताकि वे एक देश से दूसरे देश में परिवहन के दौरान माल के खो जाने/क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में माल के मूल्य की वसूली कर सकें।

एच. 2 इस मामले में, जी. ई. के पास दुनिया भर में अपने सभी ग्राहकों को रोटेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भेजे गए सामान का बीमा करने की एक विश्वव्यापी प्रथा है और इसलिए, जी. ई. ने विधिवत घोषणा की है कि नोटिसों पर उठाए गए उनके चालान में इंगित मूल्य बीमा सहित है।

एच. 3 जैसा कि इस उत्तर में पहले ही कहीं और प्रस्तुत किया जा चुका है, नोटिसकर्ताओं का कहना है कि जी. ई. द्वारा अपने चालान में घोषित मूल्य पूरी तरह से घूर्णन योग्य विनिमय कार्यक्रम के लिए जी. ई. के विश्वव्यापी मूल्य-सूची में दर्शाई गई कीमतों के अनुरूप हैं।

एच. 4 चूंकि नोटिसियों ने एल. टी. एस. ए. और रेट करने योग्य विनिमय कार्यक्रम के तहत की गई आपूर्ति के खिलाफ उठाए गए प्रत्येक चालान के लिए जी. ई. को कोई भुगतान नहीं किया है, इसलिए नोटिसियों

का कहना है कि जी. ई. द्वारा घोषित मूल्य, जिसमें माल और बीमा शामिल हैं, जो बदले में उनकी प्रकाशित मूल्य-सूची के अनुसार हैं, को नोटिसियों द्वारा आयातित हॉट पाथ गैस भागों के आंतरिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए लिया जाना चाहिए।

एच. 5 इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि जी. ई. ने आयातित गर्म पथ गैस भागों का केवल आयात चालान मूल्य की सीमा तक ही बीमा किया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने वाले जी. ई. के दिनांकित 05.02.2005 पत्र की एक प्रति अनुलग्नक-9 के रूप में संलग्न है।

एच. 6. अब यह तय कानून है कि जहां चालान मूल्यों पर संदेह है, बीमा के लिए घोषित मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत आकलन योग्य मूल्यों को निर्धारित करने का आधार हो सकते हैं।

जे. यह आश्वासन कि रोटैबल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तय की गई कीमत आधारहीन है।

जे. 1 नोटिसकर्ताओं का कहना है कि कारण बताएँ नोटिस के पैरा 29 के उप-पैरा (iv) से (vii) में यह अनुमान लगाया गया है कि मान्य विनिमय कार्यक्रम के तहत जी. ई. द्वारा पुर्जों की आपूर्ति के लिए प्रकाशित मूल्य सूचियां वापस किए गए हिस्से की कीमत में कटौती करने के बाद कीमतों को दर्शाती हैं। इस तरह की गलत धारणा का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री भी नहीं है।

जे. 2 यह अनुमान स्पष्ट रूप से श्री नरेश मनचंदा के बयान पर आधारित है जो 03.09.2003 पर दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हॉट पाथ गैस पुर्जों के प्रतिस्थापन के लिए वाणिज्यिक चालान इस बात को ध्यान में रखते हुए नोटिसियों पर उठाया गया है कि मौजूदा हिस्से को वापस भेज दिया जाएगा।

जे 3. नोटिसकर्ताओं का कहना है कि उपरोक्त बयान किसी भी तरह से निहितार्थ नहीं है जैसा कि कारण दर्शाएँ नोटिस में आरोप लगाया गया है। उपरोक्त कथन, वास्तव में, केवल मूल्यांकन योग्य विनिमय कार्यक्रम के संदर्भ में सहमत स्थिति को दोहराता है जिसके अनुसार हटाए गए हिस्से को जी. ई. द्वारा प्राप्त किया जाना है।

जे 4. नोटिसकर्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि रेटेबल एक्सचेंज प्रोग्राम स्पष्ट रूप से प्रतिस्थापन हॉट पाथ गैस पार्ट्स की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर हटाए गए हिस्से की वापसी निर्धारित करता है। कार्यक्रम में यह भी कहा गया है कि 30 दिनों के भीतर नहीं लौटाए गए हिस्सों पर कैटलॉग मूल्य का 10% अधिभार लगाया जाएगा।

जे. 5 कार्यक्रम में निर्धारित शर्त कि 30 दिनों के बाद प्राप्तियों के लिए सूची मूल्य का 10 प्रतिशत अधिभार लिया जाएगा, 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद ही लागू किया जा सकता है। इसलिए, श्री नरेश मनचंदा का बयान कार्यक्रम में समझाई गई स्थिति की पुनरावृत्ति है।

जे. 6 इसलिए, नोटिसकर्ताओं का कहना है कि श्री नरेश मनचंदा के बयान से इस आशय का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि हटाए गए हिस्से की वापसी को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन योग्य विनिमय कार्यक्रम के तहत कीमतों को जानबूझकर कम किया गया है।

जे.7 इसके विपरीत, नोटिसकर्ताओं का कहना है कि रेटेबल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हटाए गए हॉट पाथ गैस पार्ट्स की वापसी जीई की स्थापित अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुसार है और ब्रोशर में ही स्पष्ट रूप से दी गई है

जे.8 यह विभाग का मामला नहीं है कि नोटिस प्राप्तकर्ताओं ने एक मूल्य घोषित किया है जो जीई के प्रकाशित मूल्य को लौटाए गए हिस्से की कीमत से घटाकर दर्शाता है। इसलिए, नोटिसकर्ताओं का कहना है कि जब जीई की प्रकाशित कीमत को शुल्क के भुगतान के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन योग्य मूल्य के रूप में घोषित किया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि हॉट पाथ गैस पार्ट्स की वापसी ने आयातित हॉट पाथ गैस पार्ट्स की कीमत को प्रभावित किया है।

जे.9. किसी भी मामले में, नोटिस प्राप्तकर्ता श्री नरेश मनचंदा से जिरह करना चाहते हैं। इसलिए, नोटिस प्राप्तकर्ता अनुरोध करते हैं कि मामले पर निर्णय लेने से पहले श्री नरेश मनचंदा को माननीय आयुक्त द्वारा जिरह के लिए उपलब्ध कराया जाए।"

6. सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश द्वारा, विद्वान आयुक्त ने विशेष रूप से पाया कि एल. टी. ए. पी. एस. ए. के अनुसार चूंकि निर्धारिती ने केवल लौटाए गए भागों और आयातित भागों के अंतर मूल्य की घोषणा की है, इसलिए सही आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए आयातित भागों के चालान मूल्य का एक तिहाई जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार, इसने कारण दर्शाओ नोटिस में की गई मांग की पुष्टि की।

7. न्यायाधिकरण में दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया था, न्यायाधिकरण उसी निष्कर्ष पर पहुंचा था जिस पर विद्वान आयुक्त पहुंचे थे। इसके अलावा न्यायाधिकरण ने पाया कि लेन-देन का कोई मूल्य नहीं है और इसलिए, नियम 8 को संदर्भित करना होगा और उस पर भरोसा करना होगा और एक सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन किया जाना था। इसके बाद न्यायाधिकरण ने एल. टी. ए. पी. एस. ए. में एक खंड का हवाला देते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया:

"2.8 निश्चित रूप से सुधार किए गए भागों की आपूर्ति

इस समझौते के तहत अपने काम के दायरे के प्रदर्शन में, विक्रेता ऐसे पुर्जों की आपूर्ति कर सकता है जो पहले बिजली बार्ज के अलावा किसी अन्य बिजली उत्पादन सुविधा में स्थापित किए गए हैं और बाद में विक्रेता द्वारा नवीनीकृत किए गए हैं। इस तरह के नवीनीकृत भागों को विक्रेता द्वारा अनुच्छेद 8 के प्रावधानों के अनुसार वारंट किया जाएगा। विक्रेता

खरीदार की कर गणना के उद्देश्यों के लिए उन घटकों के बारे में उचित दस्तावेज प्रदान करेगा जो नए हैं, और जिनकी मरम्मत की गई है, लेकिन खरीदार सभी करों, आयात शुल्कों, मूल्य वर्धित और अन्य सभी करों का भुगतान करने के लिए बाध्य है, जो आपूर्ति, मरम्मत, नवीनीकरण, आयात, बिजली संयंत्र को वितरण और ऐसे भागों के उपयोग से उत्पन्न होते हैं। नवीनीकरण किए गए पुर्जों के संबंध में, विक्रेता खरीदार को प्रत्येक नवीनीकरण किए गए हिस्से के वृद्धिशील मूल्य के बारे में जानकारी प्रदान करेगा जो कि निर्यात किए गए तुलनीय उपयोग किए गए हिस्से के मूल्य पर है ताकि सीमा शुल्क के मूल्यांकन को ऐसे प्रत्येक नवीनीकरण किए गए हिस्से के वृद्धिशील मूल्य तक सीमित किया जा सके।

9.8 समझौतों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को विदेशी आपूर्तिकर्ता से नवीनीकृत हिस्से को प्राप्त करते समय बदले गए पुराने हिस्से का निर्यात करना आवश्यक है। उपर्युक्त पैरा 2.8 यह बहुत स्पष्ट करता है कि वाणिज्यिक चालान में प्रस्तुत मूल्य केवल एक वृद्धिशील मूल्य है और यह सीमा शुल्क के मूल्यांकन को सीमित करने के लिए भी प्रदान किया गया था। यह बहुत स्पष्ट प्रमाण है जो दर्शाता है कि आयात के समय घोषित मूल्य माल का वास्तविक मूल्य नहीं है। उक्त मूल्य को अस्वीकार करने में राजस्व सही था।

9.10. यह आग्रह किया गया है कि आयातित वस्तुओं के लिए बीमा पॉलिसी में बताए गए मूल्य को स्वीकार किया जाना चाहिए। वह मूल्य रोटेबल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मूल्य होता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कहा है कि उस मामले में, मूल्य में वापस किए गए हिस्से का मूल्य भी इस आधार पर शामिल होना चाहिए कि बीमा राशि आयातित पुर्जों और पुराने पुर्जों के बीच विभाजित की जाती है जो मेसर्स को वापस निर्यात किए जाते हैं। जी. ई. के रूप में दोनों का अपना एक मूल्य है। इसलिए, केवल आयातित भागों पर लागू बीमा राशि लेना और अपीलार्थी द्वारा तर्क दिए गए निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है।

8. निर्धारिती की ओर से पेश विद्वान वकील श्री श्रीधरन ने हमारे सामने तर्क दिया कि चालान में बताए गए मूल्य माल के बीमा होने के बाद के मूल्य थे और आमतौर पर उक्त माल के वास्तविक मूल्य का 10-15% का मार्क-अप होता है। इसलिए, अगर इन मूल्यों को ध्यान में रखा जाए, तो भी वे आयातित पुर्जों के बाजार में वास्तव में मूल्य से अधिक होंगे। उनके अनुसार, उक्त चालान जी. ई., यू. एस. ए. द्वारा एक घूर्णन योग्य विनिमय कार्यक्रम के तहत दुनिया भर में बिक्री के लिए प्रकाशित इन भागों की सूची से बनाए गए थे, जो कार्यक्रम यह स्पष्ट करता है कि ये सूची इकाई मूल्य या सूची मूल्य हैं और इसलिए, उनके स्वभाव से जी. ई., यू. एस. ए. को फिर से निर्यात किए गए भागों के कारण किया गया कोई समायोजन शामिल नहीं होगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि नियम 4

और 9 का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं था क्योंकि वास्तव में नियम 4 और इसके परिणामस्वरूप नियम 9 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए कोई "बिक्री" नहीं थी। उन्होंने कहा कि नीचे दिए गए निर्णयों में मूल दुर्बलता एल. टी. ए. पी. एस. ए. के खंड 2.8 पर निर्भरता थी। वह खंड यदि ठीक से पढ़ा जाए तो केवल निर्यात किए गए तुलनीय उपयोग किए गए हिस्से के मूल्य पर प्रत्येक नवीनीकृत हिस्से के वृद्धिशील मूल्य के बारे में "जानकारी" को संदर्भित करता है। वास्तव में, जैसा कि उत्तर में बताया गया है, चालान आयातित पुर्जों के पूर्ण मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और किसी भी समायोजित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट था कि कीमतें दुनिया भर में तय की गई थीं और उपयोग किए गए पुर्जों की किसी भी पुनः निर्यात की गई वस्तुओं का कोई संदर्भ नहीं था। उनके अनुसार, इस मामले में, आयुक्त और सी. ई. एस. टी. ए. टी. के दो निर्णय समझौते के इस खंड पर आधारित होने में पूरी तरह से गलत हैं। इसके अलावा, वे श्री मनचंदा और श्री देब के बयानों पर खुद को आधारित करने में भी गलत थे, क्योंकि उन बयानों में किसी भी तरह से निर्धारिती को दोषी नहीं ठहराया गया था, और भले ही उन्होंने ऐसा किया हो, निर्धारिती ने जिरह के लिए कहा जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इस प्रकार, इन बयानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता था और यदि ये बयान चले जाते हैं, तो वास्तव में विभाग के हाथों में सबूत के रूप में कुछ भी नहीं रहता है।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि की गई अधिकांश मांगों पर समय की पाबंदी होगी, क्योंकि कारण बताए जाने का नोटिस छह महीने की अवधि से परे था, और अधिकारियों और न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारिती की ओर से दमन के निष्कर्षों को उनके द्वारा विकृत कहा गया था क्योंकि निर्धारिती को आयात के समय किसी भी समझौते का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं थी और निर्धारिती को सीमा शुल्क विभाग द्वारा कभी भी कोई समझौता प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा गया था ताकि वे उचित रूप से कह सकें कि उसकी ओर से जानबूझकर दमन किया गया था। उन्होंने इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 17 (3) और धारा 46 (1) और (4) का उल्लेख किया। उन्होंने इस याचिका के समर्थन में कई फैसलों का हवाला दिया कि एल. टी. ए. पी. एस. ए. पेश करने में विफलता के कारण उनकी ओर से दमन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि बी. एस. ई. एस. द्वारा समान वस्तुओं का आयात किया गया था, और सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त ने दिनांक 17.4.2002 के आदेश द्वारा, बिना किसी ऐड-ऑन के आयातित वस्तुओं का चालान मूल्य लिया था। चूँकि यह आयातित समान वस्तुओं का मूल्य उसी समय या लगभग उसी समय होगा जब वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जा रहा है, सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों का नियम 5 लागू होगा और इसलिए नियम 8 का कोई भी संदर्भ गलत होगा। उक्त नियमों के नियम 5 के तहत, जैसा कि बी. एस. ई. एस. के मामले में है, केवल

आयातित वस्तुओं के चालान मूल्य को ध्यान में रखा जा सकता है, जिसमें एक तिहाई अधिक नहीं जोड़ा जा सकता है।

9. राजस्व की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री राधाकृष्णन ने इन आरोपों में से प्रत्येक का खंडन किया और हमारे सामने तर्क दिया कि मामला नियम 9 (1) (डी) और 9 (1) (ई) के साथ पठित नियम 4 (2) (जी) के अंतर्गत आता है। किसी भी मामले में, विद्वान वकील के अनुसार, भले ही किसी को सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन द्वारा जाना पड़े, यह स्पष्ट है कि आयातित वस्तुओं के एक तिहाई मूल्य को जोड़ना होगा क्योंकि समझौते के खंड 2.8 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह केवल अंतर मूल्य था जो नए भागों के आयात का मूल्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्धारिती का दायित्व है कि वह सीमा शुल्क अधिकारियों को एल. टी. ए. पी. एस. ए. का खुलासा करे क्योंकि इस तरह के समझौते को पढ़ने से दो बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आएंगी। पहला, उपयोग किए गए पुर्जों को फिर से निर्यात करना होगा और ऐसे पुर्जों का एक मूल्य होगा, और दूसरा, कि समझौते के खंड 2.8 के अनुसार, केवल आयातित पुर्जों के वास्तविक मूल्य और उपयोग किए गए पुर्जों के मूल्य के बीच का अंतर, जो निर्धारिती के अनुसार स्वयं आयातित पुर्जों के मूल्य का एक तिहाई है, आयातित वस्तुओं का चालान मूल्य होगा। उन्होंने कहा कि श्री मनचंदा का बयान स्पष्ट था और उसे लागू करना होगा और अधिकारियों और सीमा शुल्क आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा था कि चूंकि श्री मनचंदा विदेश में थे,

इसलिए उनसे जिरह नहीं की जा सकती थी, और यह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 138 बी के तहत उनके बयान को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त कारण होगा। श्री राधाकृष्णन ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि वर्तमान मामले में आयातक को आयातित वस्तुओं के मूल्य से संबंधित पूर्ण और सटीक विवरण का खुलासा करते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, इसलिए उसे पहले सीमा शुल्क अधिकारियों को पूरे एल. टी. ए. पी. एस. ए. समझौते का खुलासा करना चाहिए था जो नहीं किया गया था।

10. चूंकि कई नियमों पर निर्भरता रखी गई है, इसलिए हम सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 निर्धारित करना उचित समझते हैं जो विचाराधीन आयातों पर लागू होंगे। नियम 4 इस प्रकार है: -

4. लेन-देन मूल्य-(1) आयातित माल का लेन-देन मूल्य इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार, भारत को निर्यात के लिए बेचे जाने पर माल के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य होगा।

(2) उपरोक्त उप बी नियम (1) के तहत आयातित वस्तुओं का लेन-देन मूल्य स्वीकार किया जाएगा:

बशर्ते कि:

(छ) खरीदार द्वारा माल के किसी भी बाद के पुनर्विक्रय, निपटान या उपयोग की आय का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रेता

को नहीं मिलेगा, जब तक कि इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार उचित समायोजन नहीं किया जा सकता है।

5. समान वस्तुओं का लेन-देन मूल्य-(1) (ए) इन नियमों के नियम 3 के प्रावधानों के अधीन, डी आयातित वस्तुओं का मूल्य भारत को निर्यात के लिए बेचे गए समान वस्तुओं का लेनदेन मूल्य होगा और उसी समय या लगभग उसी समय आयात किया जाएगा जब माल का मूल्य निर्धारित किया जा रहा है।"

8. अवशिष्ट विधि-(1) इन नियमों के नियम 3 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहां आयातित वस्तुओं का मूल्य पूर्ववर्ती नियमों में से किसी के प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, मूल्य का निर्धारण इन नियमों के सिद्धांतों और सामान्य प्रावधानों और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (1) और भारत में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उचित साधनों का उपयोग करके किया जाएगा।

9. लागत और सेवाएँ-(1) लेन-देन मूल्य निर्धारित करने में, आयातित वस्तुओं के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में जोड़ा जाएगा, -

(घ) विक्रेता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित होने वाले आयातित माल के किसी भी बाद के पुनर्विक्रय निपटान या उपयोग की आय के किसी भी हिस्से का मूल्य;

(ङ) आयातित माल की बिक्री की शर्त के रूप में खरीदार द्वारा विक्रेता को या खरीदार द्वारा किसी तीसरे पक्ष को विक्रेता के दायित्व को पूरा करने के लिए वास्तव में किए गए या किए जाने वाले अन्य सभी भुगतान इस हद तक कि ऐसे भुगतान वास्तव में भुगतान या देय कीमत में शामिल नहीं हैं।

10. आयातक द्वारा घोषणा-(1) आयातक या उसका अभिकर्ता प्रस्तुत करेगा -

(क) आयातित वस्तुओं के मूल्य से संबंधित पूर्ण और सटीक विवरण का खुलासा करने वाली घोषणा; और

(ख) कोई अन्य विवरण, जानकारी या दस्तावेज जिसमें आयातित माल के निर्माता या निर्माता का चालान शामिल है, जहां माल का आयात निर्माता या उत्पादक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से या उसके माध्यम से किया जाता है, जो इन नियमों के तहत आयातित माल के मूल्य के निर्धारण के लिए उचित अधिकारी द्वारा आवश्यक माना जाता है।

11. यह ध्यान दिया जाएगा कि नियम 4 और 9 केवल उस स्थिति में लागू होंगे जब आयातित वस्तुओं को भारत को निर्यात करने के लिए

"बेचा" जाता है। "भारत को निर्यात के लिए बेचे जाने पर माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत होगी" अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप से यह मानती है कि लेनदेन मूल्य उन वस्तुओं पर आधारित होगा जो किसी विदेशी देश से भारत में निर्यात के दौरान बेचे जाते हैं। तथ्यों पर यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में कोई बिक्री नहीं है, एक ऐसा तथ्य जिसे राजस्व ने भी स्वीकार किया है। एल. टी. ए. पी. एस. ए. के तहत जो कुछ भी होता है वह यह है कि बिजली संयंत्र के चलने के कुछ निश्चित घंटों के बाद पुर्जों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदल दिया जाता है। इस मामले में, निर्धारिती के वकील का यह कहना सही है कि न तो नियम 4 और न ही नियम 9 लागू होंगे, क्योंकि नियम 4, यदि लागू होता है, तो नियम 9 को भी लागू करता है। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि नियम 4 (2) (जी) और नियम 9 (1) (डी) केवल उन्हीं वस्तुओं को संदर्भित करते हैं जो आयात की जाती हैं और उन वस्तुओं को नहीं जो आयातित वस्तुओं के लिए बहुत पहले आयात की गई हों। इसलिए, जो आवश्यक है वह यह है कि खरीदार द्वारा बहुत ही आयातित वस्तुओं की पुनः बिक्री, निपटान या उपयोग से उत्पन्न होने वाली आय होनी चाहिए। विभाग का मामला यह है कि ये उप-नियम केवल इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उस समय पहले बिक्री होती थी जब पूरे संयंत्र का आयात किया जाता था और बाद में खरीदार द्वारा संयंत्र की स्थापना के बहुत बाद आयातित वस्तुओं का निपटान किया जाता था। चूंकि यह स्पष्ट है कि

बहुत ही आयातित वस्तुओं की बाद में कोई पुनः बिक्री, निपटान या उपयोग नहीं किया गया है-यानी दिनांकित दो प्रविष्टि बिलों के तहत आयातित पुर्जे, निर्धारिती अपने तर्क में सही है कि किसी भी मामले में इनमें से कोई भी उप-नियम वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

समान रूप से, नियम 9 (1) (ई) का इस कारण से कोई आवेदन नहीं होगा कि खरीदार द्वारा विक्रेता को आयातित वस्तुओं की बिक्री की शर्त के रूप में वास्तव में कोई अन्य भुगतान नहीं किया गया है या नहीं किया जाना है। यह मामला होने के कारण, अब हमें यह देखना होगा कि क्या नियमों का नियम 5 लागू होगा जैसा कि निर्धारिती के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है।

12. हम बी. एस. ई. एस. नामक एक अन्य निर्धारिती के मामले में सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, कोच्चि द्वारा पारित दिनांक 17.4.2002 के आदेश को देख चुके हैं। उस क्रम में पूरी चर्चा केवल इस बात पर आगे बढ़ती है कि क्या विभिन्न अन्य शुल्कों को चालान मूल्य में जोड़ा जाना चाहिए और यह माना गया कि ऐसे सभी शुल्कों को इस तरह जोड़ा जाना चाहिए। हमें किसी भी तर्क या निष्कर्ष का कोई संदर्भ नहीं मिलता है कि उपयोग किए गए पुर्जों के पुनः निर्यात के कारण चालान मूल्य का एक निश्चित हिस्सा जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए यह मामला अलग करने योग्य होगा, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया

गया है। इसके अलावा, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में प्रविष्टि का बिल दिनांकित 25.6.2003 है, जो बी. एस. ई. एस. मामले में आयात के बहुत बाद का है। उस मामले में किया गया आयात वर्ष 1998 का था, जो वर्तमान आयात से चार साल पहले था, और इसलिए, माल के मूल्य पर या उसके लगभग उसी समय आयात की गई समान वस्तु नहीं होगी। इसलिए यह कहना सही है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में नियम 5 का कोई उपयोग नहीं होगा।

13. इसलिए, हमें इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि केवल नियम 8 लागू होता है, और आयुक्त द्वारा किया गया सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन उचित होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए।

14. हम पाते हैं कि आयुक्त के आदेश के साथ-साथ न्यायाधिकरण के आदेश का आधार एल. टी. ए. पी. एस. ए. का खंड 2.8 है। हम निर्धारिती के विद्वान वकील से सहमत हैं जब उसने तर्क दिया है कि विक्रेता को केवल खरीदार को प्रत्येक नवीनीकृत हिस्से के वृद्धिशील मूल्य के बारे में "जानकारी" देनी है ताकि सीमा शुल्क ऐसे प्रत्येक नवीनीकृत हिस्से के वृद्धिशील मूल्य तक सीमित हो सके। तथ्यों के आधार पर हमने पाया है कि निर्धारिती ने कारण बताओ नोटिस के अपने जवाब में यह स्पष्ट कर दिया है कि आयातित वस्तुओं की कीमत एक स्वीकार्य विनिमय कार्यक्रम मूल्य थी जो एक सामान्य समान मूल्य था जिस पर ऐसे पुर्जों

की आपूर्ति जीई, यूएसए द्वारा दुनिया भर में की गई थी। यह एक ऐसे दस्तावेज़ से स्पष्ट है जिस पर कारण दर्शाएँ नोटिस द्वारा ही भरोसा किया गया था, जो जी. ई. के अनुमोदन योग्य विनिमय कार्यक्रम से संबंधित था। उक्त दस्तावेज़ में कहा गया है: -

"प्रभावशीलता

ये कीमतें बिक्री सेवा के लिए पहले प्रकाशित सभी कीमतों का स्थान ले लेती हैं। अतिरिक्त या नई स्थापित सेवा की कीमतें उद्धरण के आधार पर उपलब्ध होंगी और इस मूल्य पत्रक के अगले अंक में शामिल किए जाने तक संशोधन के अधीन हो सकती हैं। इंगित की गई कीमतें इकाई मूल्यों की सूची हैं और बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।

हटाई गई असंबली की वापसी

जब तक कि एक वैकल्पिक अनुसूची के लिए पहले से सहमति नहीं हो जाती है, ग्राहक को अनुमोदित संपत्ति की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर जी. ई. को हटाई गई असंबली वापस करनी होगी। 30 दिनों के भीतर वापस नहीं लौटी गई सभाएं सूची मूल्य के 10 प्रतिशत के अधिभार के अधीन हैं। हटाए गए सम्मेलन जी. ई. की संपत्ति बन जाते हैं। हटाए गए असंबलियों को मरम्मत योग्य स्थिति में होना चाहिए।

15. इस दस्तावेज़ से जो स्पष्ट हो जाता है वह यह है कि वर्तमान मामले में प्रविष्टि के बिलों के साथ चालान में बताई गई कीमतें सूची

इकाई कीमतें या सूची मूल्य हैं। कल्पना के किसी भी विस्तार से उन्हें पुनः निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्य को ध्यान में रखने के बाद की कीमतें नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में, वर्तमान मामले के तथ्यों पर, आयुक्त और विद्वत न्यायाधिकरण दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलत थे कि वर्तमान मामले में चालान मूल्य केवल एक वृद्धिशील मूल्य है न कि जीई, यूएसए द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं की कीमत। तथ्यों के आधार पर यह मामला होने के कारण, हमें डर है कि आयुक्त के आदेश और न्यायाधिकरण के आदेश दोनों को केवल इसी आधार पर अलग करना होगा।

16. श्री मनचंदा के बयान और श्री देब के बयान पर भरोसा करने से, इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा क्योंकि तथ्यों के आधार पर, वाणिज्यिक चालान इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखते हैं कि मौजूदा उपयोग किए गए पुर्जों को जी. ई., यू. एस. ए. को वापस भेजा जाना है, जिसके पुर्जों का मूल्य होगा-जो आयातित वस्तुओं के चालान मूल्य का एक तिहाई है।

17. श्री राधाकृष्णन ने तर्क दिया है कि सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 के नियम 10 के तहत आयातित वस्तुओं के मूल्य से संबंधित पूर्ण और सटीक विवरण का खुलासा करते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करना निर्धारिती का दायित्व है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि नियम

10 (1) के उपखंड (बी) के तहत, निर्धारिती पर यह दायित्व था कि वह पूरे एल. टी. ए. पी. एस. ए. को सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दे और चूंकि निर्धारिती ने उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए निर्धारिती द्वारा माल के मूल्य की गलत घोषणा की गई है, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती अतिरिक्त शुल्क और जुर्माने के लिए उत्तरदायी है।

18. नियम 10 (1) जो इस निर्णय में पहले निर्धारित किया गया है, में दो उपखंड हैं। उपखंड (ए) के तहत, निर्धारिती/आयातक को आयातित वस्तुओं के मूल्य से संबंधित पूर्ण और सटीक विवरण का खुलासा करते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करनी होती है। इस उपखंड में स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 46 (4) का संदर्भ है जिसमें निम्नानुसार कहा गया है:

"(4) आयातक प्रविष्टि-पत्र प्रस्तुत करते समय ऐसे प्रविष्टि-पत्र की सामग्री की सच्चाई के बारे में घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसी घोषणा के समर्थन में आयातित माल से संबंधित चालान, यदि कोई हो, उचित अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

19. इस प्रकार धारा 46 (4) और नियम 10 (1) (ए) को एक साथ पढ़ने से आयातक पर प्रवेश पत्र प्रस्तुत करते समय इसकी सामग्री की सच्चाई के बारे में घोषणा की सदस्यता लेना और आयातित वस्तुओं से संबंधित चालान को उचित अधिकारी के समक्ष पेश करना अनिवार्य हो

जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्धारिती ने इस शर्त को पूरा किया है। श्री राधाकृष्णन द्वारा जो तर्क दिया जाना चाहिए वह यह है कि निर्धारिती को मैसर्स जीई, यू. एस. ए. के साथ किए गए एल. टी. ए. पी. एस. ए. का भी खुलासा करना चाहिए था, जो आयातित वस्तुओं के सही मूल्य और अन्य विवरणों को उचित अधिकारी को प्रकट करता, जो तब एक सूचित मूल्यांकन कर सकते थे।

20. एल. टी. ए. पी. एस. ए. एक ऐसा दस्तावेज होगा जो अधिनियम की धारा 17 (3) के साथ पठित नियम 10 (1) (बी) के अंतर्गत आता है। धारा 17 (3) इस प्रकार है:

"17(3) उप-धारा (2) के तहत शुल्क का आकलन करने के उद्देश्य से, उचित अधिकारी आयातक, निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति से कोई अनुबंध, दलाल का नोट, बीमा पॉलिसी, सूची या अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकता है, जिसके द्वारा आयातित वस्तुओं या निर्यात वस्तुओं पर देय शुल्क का पता लगाया जा सकता है, और ऐसे निर्धारण के लिए आवश्यक कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो उत्पादन या प्रस्तुत करने की उसकी शक्ति में है, और उसके बाद आयातक, निर्यातक या ऐसा अन्य व्यक्ति ऐसा दस्तावेज पेश करेगा और ऐसी जानकारी प्रदान करेगा।

21. धारा 17 (3) और नियम 10 (1) (बी) के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उचित अधिकारी आयातक से आयातित माल के संबंध

में कोई भी अनुबंध प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप आयातक ऐसा अनुबंध प्रस्तुत करेगा। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, उचित अधिकारी ने निर्धारिती को आयातित वस्तुओं के संबंध में कोई अनुबंध प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा है। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि नियम 10 का कोई उल्लंघन नहीं है जैसा कि श्री राधाकृष्णन ने तर्क दिया है।

22. चूंकि निर्धारिती योग्यता के आधार पर सफल होता है, इसलिए सीमा के बिंदु पर जाना अनावश्यक है। अतः निर्धारिती की अपील की अनुमति दी जाती है और न्यायाधिकरण के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।

राजस्व की अपील

23. विवादित फैसले में कहा गया है कि छूट अधिसूचना No.21/2002 दिनांकित 1.3.2002 निर्धारिती के मामले में लागू होगी। उक्त अधिसूचना का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

क्रम संख्या	अध्याय शीर्षक संख्या. या उप शीर्षक संख्या।	माल का विवरण	मानक दर	अतिरिक्त शुल्क डर	शर्ट संख्या
236	84 और अन्य अध्याय	बिजली उत्पादन संयंत्र के नवीनीकरण या आधुनिकीकरण के लिए सभी सामान (कैप्टिव बिजली उत्पादन संयंत्र के	5%	16%	45%

		अलावा)			
--	--	--------	--	--	--

(i) किसी विद्युत (परमाणु ऊर्जा संयंत्र को छोड़कर) के मामले में-
(क) केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में संबंधित उपक्रम का अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि ऐसे विद्युत संयंत्र के नवीनीकरण या आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी दे दी गई है और विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार के उप सचिव के पद से कम का अधिकारी प्रत्येक मामले में ऐसी योजना के लिए माल को उपरोक्त छूट देने की सिफारिश करता है।

(ख) अन्य मामलों में, संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड या राज्य विद्युत उपयोगिता के मुख्य अभियंता के पद से कम का अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि ऐसे विद्युत संयंत्र के नवीनीकरण या आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी दे दी गई है और बिजली या बिजली के पद से कम का अधिकारी, प्रत्येक मामले में, ऐसी योजना के लिए माल की उपरोक्त छूट देने की सिफारिश करता है।

(ii) परमाणु ऊर्जा संयंत्र के मामले में, परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के उप सचिव के पद से कम का अधिकारी, ऐसे बिजली संयंत्र के नवीनीकरण या आधुनिकीकरण की योजना को प्रमाणित करता है, जिसे

मंजूरी दे दी गई है और ऐसी योजना के लिए माल को उपरोक्त छूट देने की सिफारिश करता है; और

(iii) सभी मामलों में, आयातक सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त को, इस आशय का वचन देता है कि उक्त माल का उपयोग ऊपर निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा और उक्त बिजली उत्पादन संयंत्र के नवीनीकरण या आधुनिकीकरण के लिए माल का उपयोग करने में विफल रहने की स्थिति में, वह शुल्क के बीच के अंतर के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

24. मामले के इस पहलू पर न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित निर्णय दिया है: -

"10.3. राजस्व का मामला यह है कि आयात के समय आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। राजस्व का यह भी मामला है कि अपीलकर्ताओं ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। राजस्व की यह आपत्ति कि आयात के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, अधिसूचना के लाभ से इनकार करने के लिए बहुत मजबूत आधार नहीं है। ऐसे कई निर्णय हैं जिनमें विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों ने लाभ प्रदान करने के लिए आयात के बाद भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को स्वीकार किया है। अपीलार्थी ने संबंधित अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के बाद,

इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया कि नवीनीकरण की योजना की पूरी तरह से जांच की गई है और इसके लिए मंजूरी दी गई है। कर्नाटक सरकार के प्रधान सचिव ने भी उक्त अधिसूचना के तहत छूट की सिफारिश की है। अनुशंसित पुर्जों की सूची का भी उल्लेख किया गया है। कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक ने प्रमाणित किया है कि अपीलार्थी के दिनांकित 29.09.2003 पत्र में सूचीबद्ध पुर्जे उत्पादन इकाइयों के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक हैं। राजस्व का कहना है कि विवादित सामान नवीनीकरण के लिए नहीं हैं, बल्कि केवल रखरखाव के लिए हैं। हमारे विचार में, कोई भी इतना संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं ले सकता है। नवीकरण का क्या अर्थ है? नवीनीकरण का अर्थ है नया बनाना। हम घर या इमारत आदि के नवीनीकरण की बात करते हैं। वर्तमान मामले में यह बिजली संयंत्र का नवीनीकरण है। कर्नाटक सरकार को संबोधित अपने पत्र में, अपीलकर्ताओं ने कहा है कि वे अपने संयंत्र में गैस टर्बाइनों का नवीनीकरण कर रहे हैं। उस पत्र के माध्यम से जाने पर, हम नहीं पाते हैं कि कोई गलत प्रस्तुति है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि 12,500 निश्चित घंटों के बाद, नवीनीकरण आवश्यक है। हम यह भी पाते हैं कि पुराने पुर्जों का निर्यात किया जाता है और पुनर्निर्मित पुर्जों को बदलने के लिए आयात किया जाता है। एक तरह से, इसे एक प्रकार का नवीनीकरण समझा जा सकता है। किसी भी मामले में, राज्य सरकार ने अपीलार्थियों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और कर्नाटक सरकार

के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। एक बार जब सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि विवादित सामान के नवीनीकरण की आवश्यकता है, तो सीमा शुल्क विभाग को अधिसूचना के लाभ से इनकार करने के लिए बाल विभाजन और शब्दार्थ संबंधी बारीकियों में गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। डी. आर. आई. ने इस मामले को राज्य सरकार के समक्ष उठाया था, जिन्होंने योजना की मंजूरी की पुष्टि की है। एक बार बिजली परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद, हमारे विचार में, छूट अधिसूचना के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हम अधिसूचना के लाभ से इनकार करने वाले आयुक्त के आदेश को दरकिनार कर देते हैं। हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं ने उक्त अधिसूचना की शर्तों को पूरा किया है और वे इसके लाभ के लिए उचित रूप से हकदार हैं।

25. हम पाते हैं कि आवश्यक प्रमाणपत्र के साथ-साथ कर्नाटक सरकार के प्रधान सचिव की सिफारिश दोनों को उचित परिप्रेक्ष्य में निपटाया गया है। न्यायाधिकरण का यह कहना बिल्कुल सही है कि एक बार जब ये अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं कि विवादित वस्तुओं को नवीनीकरण के लिए आवश्यक है, तो सीमा शुल्क विभाग को मामले में गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है और बाल विभाजन और शब्दार्थ संबंधी बारीकियों द्वारा छूट अधिसूचना के लाभ से इनकार किया जाता है। न्यायाधिकरण द्वारा आयुक्त के निष्कर्ष को सही ढंग से दरकिनार कर

दिया गया है और इसलिए हम राजस्व की अपील को खारिज करते हैं।
इसलिए कुल मिलाकर, सी. ई. एस. टी. ए. टी. के आदेश के पैराग्राफ 11
को उपखंड (ii) और (vi) को छोड़कर अलग रखा गया है।

अपील निस्तारित की जाती है ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक हेमंत सोनी द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक एवं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।